साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 21-27 अक्टूबर 2024 वर्ष-10, अंक-27

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

-मसूर, जौ और कुसुम के लिए मिलेगा अधिक दाम, केंद्र ने रबी की छह फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को दिवाली का उपहार-एमएसपी में किया इजाफा

गेहूं पर एमएसपी 150 बढ़ी, दाम 2,425 रु. क्विंटल सरसों और तिलहन में 300 रु.बढ़ाया समर्थन मूल्य

भोपाल। जागत गांव हमार

रबी सीजन की छह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने मसूर, जौ और कुसुम फसल के लिए किसानों को उचित दाम देने के इरादे से एमएसपी दर में बढ़ोत्तरी कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने गेहूं, चना और सरसों के एमएसपी को भी बढ़ा दिया है। मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए जरूरी रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोत्तरी केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है। एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा की गई है। इस हिसाब से मार्जिन गेहूं के लिए 105 फीसदी है। इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 98 फीसदी, मसूर के लिए 89 फीसदी, चने के लिए 60 फीसदी, जौ के लिए 60 फीसदी, और कुसुम के लिए 50 फीसदी है। रबी फसलों के इस बढ़े हुए एमएसपी से किसानों को लाभकारी दाम मिलना पक्का होगा और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

किस फसल पर कितना एमएसपी बढ़ा

फसल	अब	पहले	अंतर
गेहूं	2,425	2,275	150
जौ	1,980	1,850	130
चना	5,650	5,440	210
मसूर	6,700	6,425	275
सरसों	5,950	5,650	300
कुसुम	5,940	5,800	140

नोट-एमएसपी रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से।

सबसे ज्यादा दाम सरसों का बढ़ा

केंद्रीय कैबिनेट ने रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोत्तरी को मंजूरी देते हुए 6 रबी फसलों का दाम बढ़ा दिया है। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम मिल सकेगा। एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोत्तरी रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। इसके अलावा मसूर के लिए 275 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है। इसके साथ ही चना के एमएसपी में 210 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए और सनफ्लावर यानी कुसुम के लिए 140 रुपए और जौ के लिए 130 रुपए एमएसपी प्रति क्विंटल पर बढ़ाया गया है।

पीएम के नेतृत्व वाली सरकार किसान हितैषी है। पिछले 10 वर्षों से एमएसपी में निरंतर बढ़ोत्तरी इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पित है। किसानों की आय बढ़े, उन्हें उत्पादन का उचित दाम मिले और कृषि तथा किसान का विकास हो, इसके लिए मोदी सरकार दिन-रात जुटी है। किसान हमारे लिए भगवान हैं। उनके हित में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट ने रबी विपणन सीजन 2025 - 26 के लिए 6 रबी फसलों गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों, कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का निर्णय लिया है। अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े फैसले लेने में जुटे हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने गेहूं और चना सहित अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया है। अन्नदाताओं का जीवन और आसान होगा।

वीडी शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा

प्रदेश के साढ़े सात लाख किसान बेचेंगे अपनी उपज

इधर, समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए साढ़े सात लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। गत वर्ष 7 लाख 54 हजार 384 किसानों ने पंजीयन कराया था। खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मोटे अनाज का उपार्जन 22 नवंबर और धान का उपार्जन 2 दिसंबर से किया जाएगा। किसान पंजीयन में रकबा 13 लाख 79 हजार 632 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश में हुए कुल पंजीयन में मुख्य रूप से जिला बालाघाट में एक लाख 28 हजार 327 किसान, रीवा में 61 हजार एक, सतना में 54 हजार 639, जबलपुर में 54 हजार 465, सिवनी में 54 हजार 409, कटनी में 52 हजार 171, मण्डला में 40 हजार 959, पन्ना में 33 हजार 213, शहडोल में 33 हजार 5, मैहर में 24 हजार 964, डिण्डोरी में 24 हजार 91, उमरिया में 23 हजार 662, सीधी में 23 हजार 227, सिंगरौली में 23 हजार 238, अनूपपुर में 21 हजार 679, नर्मदापुरम् में 20 हजार 636, दमोह में 19 हजार 269, मऊगंज में 17 हजार 597, नरसिंहपुर में 11 हजार 825, रायसेन में 9 हजार 334, बैतूल में 7 हजार 800, सीहोर में 6 हजार 196, सागर में 3 हजार 922, ग्वालियर में 3 हजार 630, छिंदवाड़ा में 1 हजार 876, शिवपुरी में 1 हजार 162, दतिया में 1 हजार 26, भिण्ड में 2 हजार 239, विदिशा में 880, मुरैना में 7 हजार 781 किसानों ने पंजीयन कराया है।

किसानों की शिकायत के बाद बीज कंपनी पर दर्ज किया गया केस

खरगोन में 2300 एकड़ मक्के की फसल खराब

» खरगोन के गांवों में किसानों ने एडवांटा बीज का मक्का लगाया था

» फसल में कई जगह पर तो एक भुट्टे के अंदर कुछ ही दाने निकले

खरगोन। जागत गांव हमार

खरगोन जिले के खरगोन व गोगावां तहसील में 208 किसानों ने 2300 एकड़ में लगाई मक्का फसल खराब हो गई थी। किसानों ने कृषि अधिकारियों व कलेक्टर को शिकायत की थी। शिकायत के बाद जांच हुई। इसमें शिकायत सही पाई गई। इसके चलते कृषि विभाग ने एडवांटा मक्का बीज कंपनी पर टांडाबरूड़ थाने में एफआईआर कराई है। इसमें बीज अधिनियम व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया है। उमरखली, देवली कोठा बुजुर्ग आदि गांवों में किसानों ने एडवांटा बीज का मक्का लगाया था। किसान दशरथ राठौड, कैलाश चौहान, नरेंद्र राठौड़ के अनुसार मक्का बीज में अफलन की स्थिति बनी है।

खेतों में दो से तीन इंच के भुट्टे ही लगे थे। कई जगह पर एक भुट्टे में कुछ ही दाने निकले थे। जांच के बाद बीज गुणवत्ताहीन पाए जाने पर एडवांटा कंपनी के फौजान अनीक गुलाम रहमान आवश्यक वस्तु अधिनियम व बीज अधिनियम की धाराओं के तहत टांडाबरुड़ थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। उधर, मामले में कपास बीज जांच में गुणवत्ताहीन पाए जाने पर कसरावद थाने पर संबंधित के विरुद्ध प्रकरण दर्ज है। उक्त दोनों मामलों ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

मक्का बीज की पीएसी-751 किस्म| केस में दो किस्म के बीज का उल्लेख टांडाबरुड़ थाने पर सोमवार शाम को हुई एफआईआर में फौजान अनीक गुलाम रहमान निवासी वार्ड नंबर 73 न्यू वार्ड जबलपुर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 सहित बीज अधिनियम की धारा 7 (बी) के तहत केस दर्ज किया है। एफआईआर में एडवांटा कंपनी की मक्क। बीज की पीएसी-751 किस्म सहित एक अन्य किस्म पीएसी-741 का भी उल्लेख है।

सैकड़ों किसानों को नुकसान

दोनों तहसील के करीब 12 गांवों में किसानों ने एडवांटा कंपनी की पीएसी-751 किस्म बीज लगाया था। इनमें कोठा बुजुर्ग, देवली, उमरखली, टांडाबरुड़, कुम्हारखेड़ा, नागझिरी सहित खरगोन व गोगावां तहसील के 10-12 गांव शामिल हैं।

कपास बीज भी गुणवत्ताहीन

कसरावद के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बृजेंद्र सेंगर ने बताया कि किसानों की शिकायत के बाद जांच हुई। इसमें कपास बीज अमानक पाया गया। संबंधित कंपनी संचालक पर एफआइआर दर्ज करवाई गई है। कसरावद में प्रवर्धन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर का कपास बीज किस्म पीआरसीएच 331 बीजी 2 लाट नंबर जीकेएन 421299 का सैंपल लिया गया था। जांच में बीज का एक नमूना अमानक मिला है। कसरावद की यादव कृषि सेवा केंद्र फर्म का लाइसेंस निरस्त किया गया है।

सरपंचों का बढ़ेगा अधिकार, अब कराएंगे 25 लाख तक के काम

अविश्वास प्रस्ताव चुनाव से तीन साल पहले नहीं लाए जा सकेगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश सरकार ने अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत सरपंच अब 15 लाख की जगह 25 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दे सकेंगे। पंचायत मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बताया कि अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी बदले जाएंगे। इसके लिए अब तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही, अविश्वास प्रस्ताव चुनाव से तीन साल पहले नहीं लाए जा सकेंगे। मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने बताया कि राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत भवन बनाने की योजना है, जिसमें पहले चरण में 1400 ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा, स्थानीय ग्रामीण समुदाय के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। मंत्री पटेल ने मनरेगा योजना में बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि अब श्रम सामग्री का अनुपात जनपद स्तर पर संधारित किया जाएगा, जो पहले जिला स्तर पर किया जाता था। इसके साथ ही, 25 लाख रुपए तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति अब सरपंचों को दी जाएगी, जबकि तकनीकी स्वीकृति के लिए सहायक यंत्री को अधिकृत किया गया है।

जीआरएस-सचिव की सरपंच लिखेंगे एसीआर

रोजगार सहायक और सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दिया गया है, जबकि सरपंचों को जनपद पंचायत में रोस्टर के हिसाब से 20 फीसदी प्रतिवर्ष बुलाए जाने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना ने किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल करने की दी सलाह, बोले

यूक्रेन-इजराइल में चल रहे युद्ध से एमपी में खाद संकट

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने राज्य में चल रहे खाद संकट के लिए यूक्रेन और इजराइल में चल रहे युद्ध को जिम्मेदार ठहराया है। कृषि मंत्री ने किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार ने खरीफ में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी में भी इसी प्रकार से किसानों की जरूरत के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। कंषाना ने कहा कि फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जरूरत होती है। डीएपी से नाइट्रोजन और फास्फोरस की ही पूर्ति हो पाती है, जबकि एनपीके के उपयोग से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा डीएपी के स्थान पर एनपीके के उपयोग की सलाह दी जा रही है। केंद्र ने डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ा दी है जिससे कि किसानों को किसी तरह की समस्या न हो। एक बैग यूरिया की कीमत 2 हजार 265 रुपए है, जबकि सरकार इसे सस्ते दर पर किसानों को 266.50 रुपए में उपलब्ध करा रही है। इसी प्रकार डीएपी की एक बैग की कीमत 2 हजार 446 रुपए है, जबकि सरकार इसे किसानों को 1 हजार 350 रुपए प्रति बैग उपलब्ध कराती है। मंत्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश में किसानों को खरीफ के मौसम में दी जाने वाली सब्सिडी की गणना करें तो यह यूरिया के लिए 7 हजार 32 करोड़ रुपए और डीएपी के लिए 1 हजार 258 करोड़ होगी। यह सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डीएपी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव का कारण यूक्रेन और इजराइल संघर्ष है। इनके संघर्ष के कारण आपूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ा है, फिर भी किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। कंषाना ने कहा कि खरीफ 2024 में किसानों को 32.97 लाख मीट्रिक टन की मांग के विरुद्ध 33.69 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया है, जबकि पिछले वर्ष खरीफ 2023 में 32.62 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया था। इसी प्रकार रबी 2024 में 41.10 लाख मीट्रिक टन की मांग के विरुद्ध 01 अक्टूबर 2024 से अभी तक 19 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया है। जिसमें 7.74 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.21 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 6.05 लाख मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध करा दिया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रबी 2024 के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो उर्वरकों का अग्रिम भंडारण करता है ताकि किसानों को उर्वरक की कोई कमी न हो। रबी सीजन की शुरुआत में राज्य ने पहले ही 6.55 लाख मीट्रिक टन अग्रिम भंडारण कर लिया था।

इंदौर में 12 लाख पौधे संभाल रही 50 कर्मचारियों की टीम

बारिश में पनप गए सभी पौधे, बनाया गया था विश्व रिकॉर्ड

इंदौर। जागत गांव हमार

तीन माह पहले इंदौरवासियों ने एक साथ 12 लाख पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया। उसके बाद सबसे बड़ी चिंता थी उन पौधों की साज-संभाल। पौधारोपण के तीन माह तक अच्छी बारिश में पौधे पनप गए। नगर निगम के 50 कर्मचारियों की टीम पौधों को खाद-पानी देने का काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी गर्मी के मौसम में इन पौधों को संभालना। बारिश के कारण पौधे तो पनप गए, लेकिन साथ में उगी खर-पतवार और जंगली घास भी इन पौधों का पोषण ले रही है और अभी तक उन्हें हटाया नहीं गया है।

इंदौर में 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 24 घंटे में 12 लाख पौधे लगाकर इंदौरवासियों ने आसाम का रिकार्ड तोड़ा था। वहां एक दिन में 9.21 लाख पौधे लगाए थे। इन 12 लाख पौधों को पेड़ बनने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन वे पनप जाए, इसके लिए 50 नगर निगम कर्मचारी दिन रात जुटे रहते है। सबसे ज्यादा परेशानी टेकरी पर लगे पौधों को पानी देने की है। वहां पानी से भरे बड़े टैंकर नहीं जा सकते है।

वहां दो टैंकर 24 घंटे तैनात रहते है और उनमें बोरिंग के जरिए भरा जाता है। उससे पौधों को पानी डाला जा रहा है। नगर निगम दरोगा राकेश यादव के अनुसार इस सीजन में बारिश अच्छी हुई। अक्टूबर माह में हुई बारिश भी पौधों के लिए फायदेमंद रही। ठंड के सीजन में भी पौधे और ज्यादा पनप जाएंगे। गर्मी के मौसम में इन पौधों का सबसे ज्यादा ख्याल हमें रखना होगा। टेकरी पर कनेर, चंपा,मधुकामिनी, सप्तपर्णी, कदम, नीम, कचनार,सेमल, पलाश, गुलमोहर, करौंदा,आंवला सहित अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए गए है।

नील गायों से बचाएंगे पौधे, होगी फेंसिंग

जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि 12 लाख पौधों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। टेकरी के आसपास नील गायें भी आती है। उनसे पौधों को बचाने के लिए तार फेंसिंग कराई जा रही है। इसके अलावा टेकरी पर चार बोरिंग कराए गए है। फिलहाल टैंकरों से पानी दिया जाता है। अब पाइप लाइन बिछाई जाएगी। दो सालों में पेड़ सिटी फारेस्ट का रूप ले लेंगे।

खरीफ फसल विक्रय के लिए पंजीयन का सत्यापन गंभीरता से करें: कलेक्टर

मुरैना। प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में खरीफ फसल विक्रय करने के लिये निर्धारित केन्द्रों पर कृषकों द्वारा पंजीयन कराए थे। जिसकी अंतिम तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित की थी। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर अंकित अस्थाना के मार्गदर्शन में मुरैना जिले में 61 पंजीयन केन्द्रों पर 7 हजार 53 किसानों द्वारा खरीफ फसल बेचने के लिए पंजीयन कराए थे। जिसमें धान के 448, बाजरा के 6 हजार 990 और ज्वार के 86 कृषकों ने अपनी फसल बेचने के लिये पंजीयन कराए हैं। प्रदेश सरकार के निर्देशन में बाजरा खरीदी का समर्थन मूल्य 2 हजार 625 रुपए, धान का 2 हजार 300 और ज्वार का 3 हजार 371 निर्धारित किया है। संभवत: खरीदी केन्द्रों पर 22 तारीख से खरीदी प्रारंभ की जा सकेगी। इस संबंध में कलेक्टर अंकित अस्थाना ने समस्त राजस्व अधिकारियों को गत दिवस बैठक के दौरान निर्देश दिए कि 7 हजार 53 किसानों द्वारा पंजीयन कराया है उसका सत्यापन गंभीरता से कराया जाना सुनिश्चित करें।

किसान भाई एसएसपी, कॉम्प्लेक्स एवं टीएसपी जैसे उर्वरकों के उपयोग करें

मुरैना। जिले में रबी फसलों की बोनी का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। उर्वरक फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण आदान है, जिसका संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग फसल वृद्धि एवं मृदा स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है। उप संचालक कृषि पीसी पटेल ने बताया कि विगत कई वर्षों से जिले में डीएपी उर्वरक के प्रयोग का चलन बढ़ा है। जबकि विकल्प के रुप में अन्य महत्वपूर्ण उर्वरकों जैसे एसएसपी, एनपीके कॉम्प्लेक्स का उपयोग किया जा सकता है। एसएसपी उर्वरक में फास्फोरस के साथ-साथ सल्फर तत्व भी पाया जाता है, जो पौधों में विशेषकर तिलहनी फसलों में तेल प्रतिशत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है।

ई-नर्सरी पोर्टल-उद्यानिकी क्षेत्र में एक नई पहल

पोर्टल के माध्यम से होगा पौधों का क्रय-विक्रय

भोपाल। जागत गांव हमार

घर, गार्डन या खेतों में उत्तम गुणवत्ता के पौधे लगाने के लिये, अच्छे और स्वस्थ पौध के लिए अब नर्सरी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उद्यानिकी विभाग द्वारा ई-नर्सरी पोर्टल पर 300 से अधिक नर्सरियों की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध करवाई गई है। इसके माध्यम से पौधों का क्रय-विक्रय आसानी से किया जा सकता है। नर्सरी प्रबंधन और पौध विपणन की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार की यह नई पहल है, जिसे काफी सराहा जा रहा है। संचालक उद्यानिकी एसबी सिंह ने बताया कि ई-नर्सरी पोर्टल उद्यानिकी क्षेत्र में तकनीकी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है, बल्कि राज्य के उद्यानिकी विकास में भी इसका योगदान सराहनीय है। उन्होंने बताया कि ई-नर्सरी पोर्टल पर विभाग की सभी नर्सरियों की पूरी जानकारी उपलब्ध हो गई है, जिसमें पौधवार स्टॉक रिपोर्ट, नर्सरीवार स्टॉक रिपोर्ट, पौध बिक्री रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। ई-नर्सरी पोर्टल से कृषकों और उद्यान प्रेमियों को नर्सरियों की आसान पहुंच मिल सकी है।

सिंह ने बताया कि विभागीय नर्सरियों की मान्यता, रेटिंग प्रमाणन और विस्तृत विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। जिससे नर्सरियों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से नर्सरियों की समस्त अधोसंरचनाओं का प्रबंधन और विपणन की पारदर्शिता एवं सुगमता सुनिश्चित हो रही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान संगठनों को दिया भरोसा

अन्नदाताओं के सभी सुझावों पर केंद्र सरकार करेगी अमल

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान और किसान संगठनों से संवाद के क्रम में आज नई दिल्ली में किसान संगठनों और उनके सदस्यों और अलग-अलग राज्यों के अनेकों किसान प्रतिनिधियों और किसानों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों से खेती से संबंधित कई विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई है।

चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए सभी प्रयासों सहित पिछले कल रबी की एमएसपी बढ़ाने की जानकारी किसानों को दी गई। किसान संगठनों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और कई रचनात्मक सुझाव दिए। शिवराज सिंह ने बताया, किसानों ने कहा कि मॉडल कृषि फार्म (मॉडल कृषि फार्मिंग) बनना चाहिए जिसमें यह जानकारी दी जाए कि एक-दो या ढाई एकड़ जमीन वाले किसान कैसे खेती करें और किस तरह से उसी में लाभकारी खेती करें। किसानों ने एक एकड़ वाले फार्म में ही लाभकारी खेती कर रहे किसानों के उदाहरण भी दिए। उन्होंने पानी पहुंचाने, उर्वरकों के प्रयोग, मिट्टी को स्वस्थ बनाना, प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान के कारण परेशानियां, चीनी मिलों के बंद होने और आवारा पशुओं की समस्याओं आदि को लेकर चर्चा की। किसानों ने श्रीअन्न को बढ़ावा देने को लेकर भी सुझाव दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उनके समाधान का प्रयास करेंगे।

राज्य सरकार से संबंधित विषय राज्यों को भेजेंगे और केंद्र सरकार के विषयों पर विभाग कार्रवाई करेंगे। किसानों से संवाद बहुत उपयोगी है। इस संवाद से हमें मूल समस्याओं की जानकारी सीधे किसानों से मिल रही है। साथ ही, शासकीय योजनाओं को भी किसानों तक पहुंचा रहे हैं।

-जिले में डीएपी की कमी से किसान हो रहे परेशान, -खाद खरीद केंद्र के बाहर लग रही किसानों की लाइन

पन्ना में खाद खरीद केंद्रों पर अफरा-तफरी का माहौल

भोपाल। जागत गांव हमार

रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश से खाद की किल्लत की तस्वीरें सामने आने लगी है। खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें देखी जा रही है। ताजा मामला पन्ना जिले का है। जहां किसान खाद की कमी का सामना कर रहे हैं। जिले के खाद वितरण केंद्रों में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन देखी जा रही है। किसान लाइन में घंटों बीता रहे हैं लेकिन इसके बाद भी उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। कई किसान ऐसे हैं जो कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी की खाद नहीं ले पा रहे हैं। खाद को लेकर किसानों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि कई जगहों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को ग्राउंड में उतरना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से किसानों को सलाह दी जा रही है कि वो डीएपी (डाय अमोनियम फॉस्फेट) को छोड़कर इसके अन्य विकल्पों को अपनाएं। खाद की कमी को लेकर जिला मुख्यालय के खरीद केंद्रों में भी यही स्थिति है। इसके कारण किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

किसानों को हो रही परेशानी

दिन भर लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाद नहीं मिलने के कारण किसान कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। खाद नहीं मिलने के कारण समय पर बोवनी करने में उन्हें देरी हो रही है। किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है इसलिए किसानों को खाद मिलने में परेशानी हो रही है। जबकि खाद की आपूर्ति से अधिकारी बताते हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है तो फिर किसानों को इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारी अब किसानों को डीएपी खाद का विकल्प बता रहे हैं।

डीएपी का विकल्प अपनाने की सलाह

जिले में खाद की किल्लत को लेकर पन्ना के जिला कलेक्टर ने बताया कि रबी सीजन के लिए जिले में डीएपी खाद की सप्लाई मांग के अनुरूप नहीं हुई है, पर फिर भी सभी तहसीलो को खाद मिल रही है। किसानों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि वे डीएपी की जगह नैनो यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। वहीं खाद लेने के लिए लाइन में खड़े किसान सोनेलाल ने कहा कि एक दिन पहले से लाइन में खड़े में हैं, आधार कार्ड जमा है लेकिन अब वो पता मांग रहे हैं। महेबा के किसान रामकेश सिंह राजपूत ने बताया कि सुबह से लाइन में लगे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उनके पास 10 एकड़ जमीन है लेकिन सिर्फ तीन बोरी डीएपी उन्हें मिली है।

80 हजार हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी

पोर्टल पर फसल का रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं, 784 किसानों के हुए पंजीयन

दमोह। जागत गांव हमार

दमोह जिले में पोर्टल पर फसल का रिकार्ड दर्ज न होने और सर्वर डाउन होने से किसानों की सोयाबीन की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं। जबकि 80 हजार हेक्टेयर में इस बार सोयाबीन की बोनी की गई है। बता दें गेहूं कि तरह इस साल पहली बार सोयाबीन की फसल भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। इसके लिए 25 अक्टूबर से खरीदी शुरू होगी, लेकिन बार-बार सर्वर डाउन होने एवं गिरदावरी को पोर्टल पर अपलोड न किए जाने से अभी तक महज 784 किसानों का ही पंजीयन हो पाया है, जिससे किसानों को पंजीयन कराने के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इधर, पंजीयन में आ रही दिक्कतों की वजह से किसान मंडी में ही अपनी उपज लेकर पहुंचने लगे हैं। शहर के सागर नाका कृषि उपज मंडी में अन्य फसलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा सोयाबीन की आवक हो रही है। जहां पर किसानों को समर्थन मूल्य से 500 से 600 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य का रेट 4,892 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जबकि मंडी में किसानों को 4,280 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिल रहे हैं। दमोह जिले में इस बार 80 हजार हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी की गई थी। ऐसे में 25 हजार किसानों के पंजीयन होना है। लेकिन अभी तक नाममात्र के पंजीयन हुए हैं। मंडी पहुंचे किसान सुरेश ने बताया कि पहले भी दो बार आ चुके हैं। उस समय बताया गया था कि गिरदावरी अपडेट नहीं हुई है, जिससे प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। अब सर्वर डाउन बता रहा है। शहर के निजी साइबर कैफे संचालक ने बताया कि अधिकांश किसानों फसल की गिरदावरी पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है, जिससे पंजीयन में बार-बार समस्या आ रही है। कई किसानों के खसरा नंबर तो कई किसानों की फसल गलत दर्ज है, जिससे पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं। 20 किसानों में से महज 4 से 5 किसानों का ही पंजीयन हो पाता है।

कृषि उपज मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंचने लगे

समर्थन मूल्य की खरीदी में अभी 10 दिन का समय शेष है। ऐसे में किसान कृषि उपज मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंचने लगे हैं। पालर गांव निवासी किसान वीरेंद्र पटेल, तीरथ पटेल ने बताया कि रबी सीजन की फसल की बोवनी के लिए खाद, बीज के लिए पैसों की जरूरत है। इसलिए मंडी में उपज लेकर आए हैं। ताकि समय पर बोवनी कर सकें। किसान राजेंद्र लोधी ने बताया कि पंजीयन कराने में काफी झंझट हो रही है। इसलिए मजबूरी में मंडी में उपज लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि कई व्यापारी तो गांव से ही उपज ले जा रहे हैं।

गिरदावरी के बाद होता है पंजीयन

कृषि विभाग के सलाहकार गिरवर पटेल ने बताया कि गिरदावरी के जरिए किसानों को फसल बीमा और उपार्जन जैसी योजनाओं में फायदा मिलता है। गिरदावरी में किसान की जमीन के कुल क्षेत्रफल में बोई गई फसल का नाम दर्ज किया जाता है। इसके लिए पटवारी गांव के भूमि मालिकों और सिकमी/बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों की मौजूदगी में जमीन का निरीक्षण करता है। इसमें कुल रकबे में बोई गई फसल ऑनलाइन दर्ज कराई जाती है। इसके लिए किसान का नाम, खेत का सर्वे नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। गिरदावरी होने के बाद ही वह अपनी उपज बेचने के लिए पंजीयन करा सकता है।

किसानों को किफायती दामों पर सीड सप्लाय हो

सोयाबीन की नई वैरायटीज को लेकर मल्टीपल डेवलपमेंट जरूरी

इंदौर। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की पुरानी किस्मों के कमजोर उत्पादन और गुणवत्ता में गिरावट ने कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है। सोयाबीन प्रोडक्शन में यह कमी सीड क्वालिटी की गिरावट का नतीजा है, जिसे सुधारने की सख्त जरूरत है। सोपा (सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के डिप्टी चेयरमैन नरेश गोयनका ने इंदौर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव के दौरान से बातचीत में यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया।

गोयनका ने कहा कि सोयाबीन की नई वैरायटीज डेवलप हो रही हैं, लेकिन उनका व्यापक रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। हमें सरकार से उम्मीद है कि वह सीड क्वालिटी डेवपलर्स के साथ समन्वय कर इन किस्मों को किफायती दामों पर किसानों को उपलब्ध कराएगी। आने वाले तीन-चार सालों में ही इन प्रयासों से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

इंदौर में आयोजित दो दिवसीय सोया इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव का सोमवार को समापन हुआ। इस साल कॉन्क्लेव की थीम एडिबल ऑइल्स और प्रोटीन-विजन 2030 पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य सोया इंडस्ट्री की चुनौतियों और नए अवसरों पर विचार-विमर्श करना था। कार्यक्रम में भारत सरकार के सीएसपी (कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस) के चेयरमैन प्रो. विजय पॉल शर्मा मुख्य अतिथि थे, जबकि मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी शिरकत की।

किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो इण्डस्ट्रीज की ग्रोथ होगी

मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा, हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है और किसानों की समृद्धि से ही उद्योगों की प्रगति संभव है। इंदौर स्वच्छता में सात बार देश में पहले स्थान पर रहा है, और सोयाबीन उत्पादन के मामले में भी भारत दूसरे स्थान पर है। हालांकि, हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम पहले स्थान पर आ जाएंगे। देश में अन्नदाता हैं, तो हम हैं। सोया का संबंध उद्योगपतियों और अन्नदाताओं से ही है। जितनी बेहतर सुविधाएं अन्नदाता किसानों को मिलेगी, उतनी ही अच्छी इंडस्ट्री उद्योगपतियों की चलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अन्नदाताओं के हित में काम कर रहे हैं। हमें किसी भी संबंध में विदेश जाने की जरूरत न पड़े। सोपा इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

जलवायु परिवर्तनः अंटार्कटिक में नाटकीय रूप से बढ़ रही हरियाली

आमतौर पर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हरियाली का बढ़ना इस बात का सबूत है कि वहां पर्यावरण तेजी से फल फूल रहा है। लेकिन अंटाकर्टिक में बढ़ती हरियाली ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। इस बारे में किए एक नए अध्ययन से पता चला है कि अंटार्कटिक में हरियाली नाटकीय रूप से बढ़ रही है, जिसमें पिछले चार दशकों के दौरान दस गुणा से ज्यादा की वृद्धि हुई है। रिसर्च से पता चला है कि अंटार्कटिक क्षेत्र, वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इतना ही नहीं यहां भीषण गर्मी की घटनाएं बेहद आम होती जा रही हैं। एक्सेटर और हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के साथ-साथ ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण से जुड़े शोधकर्ताओं द्वारा किए इस अध्ययन में इस बात की जांच की गई है कि पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन के चलते इस क्षेत्र के पर्यावरण में कितना बदलाव आया है और वहां मौजूद हरियाली में कितना इजाफा हुआ है। अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों की भी मदद ली है।

इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं, उनसे पता चला है कि इस प्रायद्वीप पर वनस्पति का आवरण जो 1986 में एक वर्ग किलोमीटर से भी कम था, वो बढ़कर 2021 तक करीब 12 वर्ग किलोमीटर हो गया। अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित इस अध्ययन के नतीजे यह भी दर्शाते हैं कि 1986 से 2021 की तुलना में 2016 से 2021 के बीच हरियाली के बढ़ने की दर में 30 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है, तथा इस दौरान हरियाली में सालाना 400,000 वर्ग मीटर से अधिक का विस्तार हुआ है। अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर काई-प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र पर किए पिछले अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि हाल के दशकों में पौधों की वृद्धि दर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। वहीं इस नए अध्ययन में उपग्रह से प्राप्त छवियों से पुष्टि हुई है कि अंटार्कटिक में हरियाली तेजी से बढ़ रही है। इस बारे में एक्सेटर विश्वविद्यालय और अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता डॉक्टर थॉमस रोलैंड ने प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा, अंटार्कटिक पर पाए जाने वाली वनस्पति, जिनमें से अधिकांश काई हैं, पृथ्वी पर सबसे कठोर परिस्थितियों में उगती हैं। उनके मुताबिक इस भूदृश्य अभी भी अधिकांश हिस्सा बर्फ और चट्टानों से ढंका है, वहीं केवल एक छोटा से हिस्से में वनस्पति मौजूद है। हालांकि यह छोटा सा हिस्सा अब नाटकीय रूप से बढ़ रहा है, जो दर्शाता है कि यह विशाल निर्जन बर्फका 'जंगल' भी इंसानों की वजह से होते जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित नहीं है और बड़ी तेजी से प्रभावित हो रहा है।

जलवायु परिवर्तन से अंटार्कटिक के पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे हैं व्यापक बदलावः वहीं इस बारे में हर्टफोर्डशायर विश्वविद्यालय से जुड़े डॉक्टर ओली बार्टलेट ने प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से जानकारी दी है कि, जैसे-जैसे ये पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ते जाएंगे और जलवायु गर्म होती जाएगी, हरियाली का क्षेत्र कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। उनके मुताबिक अंटार्कटिका में ज्यादातर मिट्टी या तो अनुपजाऊ है या मौजूद ही नहीं है, लेकिन पौधे के बढ़ने के साथ कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे, जो मिट्टी बनने में मदद करेंगे। इसकी वजह से अन्य पौधों के उगने और बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। वैज्ञानिकों ने इस बात की भी आशंका जताई है कि इससे विदेशी आक्रामक प्रजातियों के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा, जो संभवतः पर्यटकों, वैज्ञानिकों या महाद्वीप के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोगों के जरिए यहां पहुंच सकती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने हरियाली की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए जिम्मेवार जलवायु और पर्यावरणीय कारकों को समझने के लिए और अधिक अध्ययन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। डॉक्टर रोलैंड के मुताबिक, यह अब स्पष्ट हो चुका है कि अंटार्कटिक में पौधे जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। भविष्य में हम इंसानों की वजह से बढ़ती गर्मीके चलते इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र के परिदृश्य और जीवों में व्यापक बदलाव सामने आ सकते हैं।

पराली से खाद बनाने की तकनीक बचेगा यूरिया और डीएपी का पैसा

देश में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और हर साल फसल कटाई के बाद पराली की समस्या सामने आती है। कई किसान इसे जलाकर निपटाते हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाते हुए पूर्ण प्रतिबंध का लक्ष्य रखा है। पराली जलाने से निजात पाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली से खाद बनाने की तकनीक विकसित की है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तकनीक से अब किसान पराली से खाद बनाकर अपने खेत से बिना डीएपी, यूरिया या अन्य रासायनिक खादों के बेहतर फसल उगा सकते हैं। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि किसानों का उवर्रक पर खर्च भी कम होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बायोमास यूटिलाइजेशन यूनिट के कोऑर्डिनेटर और प्रमुख वैज्ञानिक डा. शिवधर मिश्रा ने जानकारी दी कि वायवीय विधि, जिसे विंड्रोव कम्पोस्टिंग कहा जाता है, जिसके माध्यम से पराली से बड़े पैमाने पर और कम समय में बेहतर खाद बनाई जा सकती है। यह खाद न केवल मिट्टी को नरम बनाती है, बल्कि खेतों में लंबे समय तक पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखती है।

पराली से उपजाऊ खाद बनाने के 3 तरीकेः विंड्रोव कम्पोस्टिंग एक सरल और प्रभावी तकनीक है, जिससे किसान पराली और अन्य फसल अवशेषों से आसानी से जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में पराली का ढेर बनाकर उसे समय-समय पर पलटा जाता है, जिससे उसमें वायु का संचरण बना रहता है और कम्पोस्ट जल्दी तैयार हो जाती है। तीन विधियों से विंड्रोव कम्पोस्टिंग की जा सकती है- **1. जैविक कल्चर विधि :** इस विधि में पराली का ढेर बनाकर उसे समय-समय पर पलटा जाता है, जिससे उसमें वायु का संचरण बना रहता है और कम्पोस्ट जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें जैव-एंजाइम पूसा का छिड़काव किया जाता है। ढेर की ऊंचाई 2-2.5 मीटर और लंबाई 10 से 100 मी. या उससे अधिक हो सकती है। नमी बनाए रखने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है और मशीनों से पलटाई की जाती है। इस प्रक्रिया में 4 से 5 हफ्तों में जैविक खाद तैयार होती है।

2. पराली गोबर मिश्रण विधि : इस विधि में 80 फीसदी पराली और 20 फीसदी ताजे गोबर को मिलाकर खाद बनाई जाती है। पराली को लगभग 8-10 सेंमी लंबाई में काटकर ढेर बनाया जाता है और उसमें गोबर मिलाया जाता है। इसके बाद जैविक कल्चर मिलाया जाता है। यह विधि सरल और प्रभावी है, जिसमें 4 से 5 हफ्तों के भीतर उत्तम जैविक खाद तैयार हो जाती है।

3. रॉक फॉस्फेट युक्त समृद्ध खाद : इस विधि में पराली और गोबर के साथ रॉक फॉस्फेट का उपयोग होता है, इसके बाद जैविक कल्चर मिलाया जाता है। यह फॉस्फो-कम्पोस्ट पौधों के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। 4 से 5 हफ्तों में खाद तैयार होती है।

पराली से खाद बनाने की प्रक्रियाः खाद बनाने की पूरी प्रक्रिया में पराली के ढेर की ऊंचाई और लंबाई उपलब्ध स्थान के अनुसार तय की जाती है। जैविक कल्चर मिलाने के बाद पर्याप्त नमी बनाए रखी जाती है और मशीनों या हाथों से समय-समय पर पलटाई की जाती है। डॉ। शिवधर मिश्रा के अनुसार पराली के ढेर में डालने के तुरंत बाद पहली पलटाई की जाती है ताकि सभी अवशेष समान रूप से मिल सकें। इसके बाद दूसरी पलटाई 10 दिन बाद, तीसरी 25 दिन बाद, चौथी 40 दिन बाद और पांचवीं 55-60 दिन बाद की जाती है। पलटाइयों की संख्या और समय अंतराल पराली की स्थिति और आवश्यकता के आधार पर घटाई-बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार 60 से 70 दिनों के भीतर तैयार की गई कम्पोस्ट खेत में डालने के लिए तैयार हो जाती है। पराली से बनी कम्पोस्ट खाद किसानों के लिए एक लाभकारी विकल्प है। इससे न केवल मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि किसानों का उर्वरक पर खर्च भी कम होता है और पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है।

पालतू कछुओं की देखभाल और उचित प्रबंधन

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
» डॉ. जितेंद्र सेहरावत
» डॉ. आकाश सुमन
» डॉ. अनिल धाकड़
» डॉ. आकाश सेंगर

पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू, इंदौर मप
पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, आनंद, गुजरात

पालतू कछुए एक अद्भुत और आकर्षक विकल्प हैं। इनकी खासियत यह है कि ये शांत, लंबे समय तक जीने वाले और बेहद दिलचस्प जीव हैं। हालांकि, कछुओं की देखभाल करना एक जिम्मेदारी है और इसके लिए सही जानकारी की आवश्यकता होती है। कछुओं के लिए एक उचित आवास सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। उनका टैंक आकार उनके प्रकार पर निर्भर करता है। छोटे कछुओं के लिए 20-30 गैलन का टैंक पर्याप्त हो सकता है, जबकि बड़े कछुओं के लिए 75 गैलन या उससे अधिक का टैंक आवश्यक है। टैंक में पानी की गहराई, कछुए के आकार और प्रजाति के अनुसार होना चाहिए।

कछुओं के लिए साफ और ताजे पानी का होना आवश्यक है। टैंक में पानी का स्तर नियमित रूप से जांचें और उसे साफ रखें। पानी में फिल्टर लगाना बहुत फायदेमंद होता है। सप्ताह में एक बार पानी को पूरी तरह से बदलें और टैंक के फर्श की सफाई करें।

तापमान और प्रकाशः कछुओं के लिए सही तापमान और प्रकाश व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। टैंक में एक गर्म स्थान और एक ठंडा स्थान होना चाहिए। कछुओं के लिए दिन में 10-12 घंटे की रोशनी जरूरी है। इसके लिए विशेष लाइट का उपयोग करें, जो कछुओं की हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होती है।

तापमान की आवश्यकताएंः गर्मी के लिए, टैंक के एक हिस्से में हीटिंग लैंप लगाना चाहिए, जो तापमान को 80-90°F (27-32°C) तक बनाए रखे। ठंडे हिस्से का तापमान 70-75°F (21-24°C) होना चाहिए।

आहारत्र कछुओं का आहार उनकी प्रजाति के अनुसार भिन्न होता है। कुछ कछुए शाकाहारी होते हैं, जबकि अन्य मांसाहारी। उनके लिए संतुलित आहार प्रदान करना आवश्यक है। ताजे हरे पत्तेदार सब्जियाँ, फल, और विशेष रूप से तैयार कछुआ फूड का उपयोग करें।

विटामिन और सप्लीमेंट्सः कछुओं को विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और विटामिन डी3 महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें खाने में मिलाने से कछुओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है।

स्वास्थ्य देखभालः कछुओं की स्वास्थ्य देखभाल भी एक आवश्यक पहलू है। नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की जांच करें। यदि आपको उनके व्यवहार में कोई असामान्यता दिखाई दे, जैसे कि खाने से इनकार करना या ऊर्जा में कमी, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें।

बीमारी की पहचानः कछुओं में कुछ सामान्य बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि श्वसन संक्रमण, स्किन इंफेक्शन, और पाचन समस्याएँ। इन लक्षणों के प्रति सजग रहना आवश्यक है। अगर कछुआ सुस्त या परेशान दिखता है, तो इसकी जांच करवाना जरूरी है।

सामाजिक व्यवहारः कछुए आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियाँ सामाजिक होती हैं। यदि आप एक से अधिक कछुए रखने की सोच रहे हैं, तो उनके स्वभाव और आकार के अनुसार जोड़ी बनाना महत्वपूर्ण है।पालतू कछुओं की देखभाल एक चुनौती हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और प्रबंधन के साथ, यह एक अद्भुत अनुभव बन सकता है। अपने कछुए की जरूरतों को समझना और उनकी उचित देखभाल करना उनके स्वास्थ्य और खुशी के लिए आवश्यक है। यदि आप इनकी देखभाल में सही ढंग से ध्यान देंगे, तो आपके कछुए लंबे समय तक आपके जीवन का हिस्सा बने रहेंगे और आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगे।

पालतू कछुए का सामान्य रखरखावः क्योंकि कछुए विदेशी पालतू जानवर हैं, इसलिए आपको अपनी प्रजाति के लिए खास तरह का भोजन बेचने वाला पालतू जानवर का स्टोर खोजने में मुश्किल हो सकती है। फीडर मछली महंगी हो सकती है और वे टैंक को गंदा कर सकती हैं; कछुए आम तौर पर लापरवाही से खाते हैं, और आपको खुद को छोटे पत्थरों के नीचे से सड़ते हुए मछली के कणों को चुनना पड़ सकता है। कछुए के आवास को भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपका कछुआ अपने तैरने और/या पीने के पानी में शौच करेगा, इसलिए नियमित रूप से उसका पानी बदलना ज़रूरी है। इसके अलावा, आपको अपने जलीय कछुए के टैंक में नियमित रूप से पानी को फ़िल्टर करना सुनिश्चित करना चाहिए या अपने स्थलीय कछुए के बाड़े से किसी भी फफूंदयुक्त पौधे के मलबे को साफ करके निकालना चाहिए।

मिट्टी के सूखने और गर्म होने की घटनाओं में भारी वृद्धि, पौधों और जीवों पर संकट

मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और यह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाती है। पौधों की जड़ों को सहारा देती है और कई सूक्ष्मजीवों को आश्रय देती है। गमज़ होती दुनिया में यह समझना जरूरी है कि मिट्टी की नमी और सूखे की परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं।

यह शोध चीनी अकादमी ऑफसाइंसेज के नानजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड लिम्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। शोध में 1980 से 2023 तक दुनिया भर में मिट्टी पर सूखे और भयंकर गर्मी का असर, जिसे सॉइल कंपाउंड ड्राउट - हीटवेव कहा जाता है, इससे संबंधित घटनाओं की मात्रा तय की गई है, साथ ही इस सदी के अंत तक वह किस तरह और बढ़ेगी इसका पूर्वानुमान जारी किया गया है। शोधकर्ताओं ने अतीत और भविष्य में दुनिया भर में मिट्टी पर सूखे और भयंकर गर्मी के असर के रुझानों और बदलावों का विश्लेषण किया। शोध में कहा गया है कि इसमें लंबे समय के आंकड़ों को भी शामिल किया गया है। शोधकर्ताओं ने पिछले 44 सालों में मिट्टी पर सूखे और भयंकर ग की घटना दर, अवधि, चरमता और गंभीरता के साथ-साथ दुनिया भर में प्रभावित क्षेत्र में हो रही बढ़ोतरी का भी खुलासा किया। शोध में कहा गया है कि 1980 से 2023 तक, विशेष रूप से इस सदी में मिट्टी पर सूखे और भयंकर गर्मी में भारी वृद्धि देखी गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग ने इसमें बड़ी जिम्मेदारी निभाई और एल नीनो वाले सालों में स्थिति और भी बदतर हुई है। शोधकर्ता ने शोध के हवाले से बताया कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मिट्टी पर सूखे और भयंकर गमीज़ में वृद्धि गमिज़यों के मौसम पर आधारित थी, जो जल सुरक्षा के लिए एक भारी चुनौती है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि मिट्टी पर सूखे और भयंकर गर्मी का बहुत ज्यादा असर देखा गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि सामान्य तौर पर, उत्तरी गोलार्ध में सॉइल कंपाउंड ड्राउट - हीटवेव (एससीडीएचडब्ल्यू) अधिक तीव्र थे और यह दक्षिणी गोलार्ध में लंबे समय तक बने रहे। उत्तरी उच्च अक्षांशों में एससीडीएचडब्ल्यू की गंभीरता तेजी से बढ़ी, जहां मिट्टी का तापमान आमतौर पर कम था और गर्मी का असर साफदिखा। ये घटनाएं उत्तरी गोलार्ध में कार्बन पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लक्ष्यों और दक्षिणी गोलार्ध में खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को खतरे में डाल सकती हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जंगलों का क्षरण और नमी वाली जमीन को कृषि भूमि में बदले जाने से एससीडीएचडब्ल्यू का खतरा और बढ़ जाएगा। जलग्रहण प्रबंधन के लिए मिट्टी को सूखने और अधिक गर्म होने से बचाने के लिए स्थायी नीतियों और कार्यों की आवश्यकता होती है।

स्ट्रॉबेरी की फसल ने किसान बाबूलाल की आर्थिक स्थिति को किया मजबूत

भोपाल। जागत गांव हमार

धार जिले में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को उद्यानिकी फसलों की तरफ प्रेरित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मिशन के माध्यम से धार जिले के बदनावर के ग्राम तिलगारा के किसान बाबूलाल पाटीदार की आर्थिक स्थिति में प्रगतिशील बदलाव आया है।

किसान बाबूलाल पाटीदार वर्षों से अपने खेतों में पारम्परिक खेती कर सोयाबीन और गेहूं की फसल लिया करते थे। मेहनत के मुकाबले उन्हें खेती में मुनाफा नहीं हो पाता था। उन्होंने इस बात को लेकर उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारियों ने उनके खेत के परीक्षण के बाद स्ट्रॉबेरी की फसल लेने की सलाह दी। किसान बाबूलाल को

एकीकृत बागवानी विकास मिशन में मिलने वाले लाभों की जानकारी भी दी गई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक हेक्टेयर क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई। किसान बाबूलाल ने स्ट्रॉबेरी की खेती के दौरान मल्चिंग तथा ड्रिप पद्धति का उपयोग किया और अधिकारियों के मार्गदर्शन में खाद का उपयोग भी किया। किसान बाबूलाल ने 180 क्विंटल स्ट्रॉबेरी की फसल ली। स्ट्रॉबेरी की फसल बेचकर उन्हें 2 लाख रुपए से अधिक का मुनाफा हुआ। बाबूलाल पाटीदार बताते हैं कि उन्होंने स्ट्रॉबेरी को जयपुर, भोपाल और इंदौर मंडी में विक्रय किया। कई खरीददार तो हमारे खेत से ही स्ट्रॉबेरी ले गये। उन्होंने बताया कि पहली बार तो वे स्ट्रॉबेरी के पौधे खरीदकर लाए थे, लेकिन इस वर्ष तो मदर प्लांट से पौधे तैयार कर लिए गए हैं।

सरकार से 12 लाख मिला अनुदान

किसान बाबूलाल बताते हैं कि खेती को वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए तो कृषि उपज से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। उन्हें स्ट्रॉबेरी फसल लगाने के लिए राज्य सरकार से एक लाख 12 हजार रुपए का अनुदान भी मिला, जो कृषि कार्य के लिए उपयोगी साबित हुआ। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में किसान ऑनलाइन पंजीयन MPFSTS पोर्टल के माध्यम से http://mpfsts.mp.gov.in पर पंजीयन करा सकते हैं। साथ ही उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू के नवीन कन्या छात्रावास का लोकार्पण

गौ- सेवा हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान दिला सकती है : पशुपालन मंत्री पटेल

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने कहा है कि गौ- सेवा हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान दिला सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन के कार्य निरंतर जारी है। इस वर्ष हमारी सरकार गौ- संरक्षण एवं संवर्धन वर्ष भी मना रही है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इस क्षेत्र में अपना पूरा-पूरा योगदान दे।

मंत्री पटेल ने महू में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय के नवीन कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया। मंत्री पटेल ने पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय की विभिन्न इकाईयों हॉस्पिटल, डेयरी फार्म, मुर्गी फार्म, बालक एवं बालिका छात्रावास का भ्रमण किया तथा महाविद्यालय की गतिविधियों का जायजा लिया। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु प्रोफेसर (डॉ.) मनदीप शर्मा भी उपस्थित थे।

मंत्री पटेल ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से बात कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना और हल किया। उन्होंने इंटर्नशिप छात्रों का मानदेय बढ़ाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने महाविद्यालय की समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। मंत्री पटेल ने महाविद्यालय द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे विद्यार्थी

कुलगुरु डॉ. शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य सुनील मानसिंका ने भी उद्बोधन दिया। सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. बीपी शुक्ला ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। महाविद्यालय की उपलब्धियां एवं गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान विश्वविद्यालय के संपदा अधिकारी डॉ. एस के कारमोरे, अस्सिटेंट रजिस्टार रामकिंकर, जिला पंचायत सदस्य दिनेश सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। संचालन डॉ. संदीप नानावटी ने किया और आभार डॉ. हेमंत मेहता ने माना।

प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माना आभार

केन्द्र सरकार द्वारा छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के लिए आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि अन्नदाता को प्राथमिकता मोदी सरकार का संकल्प है। नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्री-मंडल की बैठक में रेपसीड और सरसों के लिए एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि 300 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 275 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है। चने में 210 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल, कुसुम में 140 रूपये प्रति क्विंटल एवं जौ में 130 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश और देश के किसानों की ओर से इस फैसले का अभिनन्दन किया है। मख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में किसानों के लिए विगत 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिससे अन्नदाता निरंतर खुशहाल और समृद्ध हो रहा है। केन्द्रीय मंत्री-मंडल की बैठक में गेहूं का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2275 रुपए से बढ़ाकर 2425 रुपए, जौ का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1850 रुपए से बढ़ाकर 1980 रुपए, चने का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 5440 रुपए से बढ़ाकर 5650 रुपए, मसूर का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 6425 रुपए से बढ़ाकर 6700 रुपए, रेपसीड और सरसों का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 5650 रुपए से बढ़ाकर 5950 रुपए और कुसुम का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 5800 रुपए से बढ़ाकर 5940 रुपए किया गया है।

प्रदर्शन तिलहन के अंतर्गत 204 प्रदर्शन किसानों के प्रक्षेत्रों पर लगाए गए

समूह दलहन व तिलहन प्रदर्शनों का जिले के आदर्श ग्रामों में भ्रमण

नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर के द्वारा दलहन आदर्श ग्राम (अरहर), तिलहन आदर्श ग्राम (सोयाबीन व तिल), समूह प्रदर्शन दलहन व तिलहन योजना अंतर्गत ग्राम सुपला, मानेगांव, गोबरगांव, आलोद में किसानो के प्रक्षेत्रों पर क्रमशः सोयाबीन, अरहर, रामतिल एवं तिल पर प्रदर्षन लगाए जिसके निरिक्षण के लिए भाकृअनुप निदेषालय कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान जबलपुर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. शालिनी चक्रबोरती के साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. विशाल मेश्राम, डॉ. एसआर शर्मा, डॉ. आशुतोष शर्मा 8 अक्टूबर 2024 को उपरोक्त ग्रामों के किसानों से दिए गए विभिन्न प्रजातियां के गुण दोष के बारे में चर्चा किया। सोयाबीन के अंतर्गत दो प्रजातियां क्रमशः जेएस 20-116, जेएस 21-72 दी गई थी जिसमें जेएस 21-72 का प्रदर्शन अच्छा पाया गया। अरहर के अंतर्गत जीआरजी152 मध्यम देर से पकने वाली जाति का प्रदर्शन लगाया गया जो बहुत अच्छी पाई गई। खरीफ मौसम में जिले में तिलहनी

फसल के रुप में सिर्फ सोयाबीन लिया जाता था जिसका उत्पादन विगत कई वर्षों से कम रहा को देखते हुए रामतिल व तिल तिलहनी फसल जिले में लगवाई गयी जिसकी बढवार व पैदावार अच्छा आने की उम्मीद है। डॉ. शालिनी चक्रबोरती द्वारा प्रदर्शन लगाए गये विभिन्न ग्रामों के किसानों से चर्चा उपरांत किसानों ने बताया की प्रदर्शन में प्राप्त बीज कि गुणवत्ता अच्छी थी जिससे पैदावार सोयाबीन में 8-10 क्विंटल प्रति एकड आने कि उम्मीद है तिल व रामतिल दोनों नई तिलहनी फसल जिले के अंतर्गत लगाई गई का पैदावार अच्छा मिलने की उम्मीद है।

समूह तिलहन प्रदर्शन के अंतर्गत 75 प्रदर्शन लगाए गए जबकी समूह प्रदर्शन तिलहन के अंतर्गत 204 प्रदर्शन किसानों के प्रक्षेत्रों पर लगए गए। कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा सभी योजनाओं के अंतर्गत कुल 450 प्रदर्शन लगवाए गए जिनका उत्पादन निरिक्षण के समय अच्छी आने की उम्मीद पाई गयी एवं डॉ. शालिनी द्वारा किसानों को अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन दिए गए। डॉ. शालिनी चक्रबोरती द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र पर लगाए गए प्रजनन एवं प्रमाणित प्रदर्शनों का अवलोकन एवं विभिन्न इकाइयों जैसे बागवानी, प्राकृतिक खेती, केंचुआ खाद उत्पादन एवं फसल संग्रहालय का भ्रमण केन्द्र के वैज्ञानिकों के साथ ही रजनीप्रभा कोरी, रिंकी झारिया द्वारा करवाया गया।

मछली पालक भाईयों हेतु समसामयिकी सलाह

बदलते मौसम के दौर में बेहोश होकर तालाब के किनारे मर रही हैं मछलियां

टीकमगढ़ । जागत गांव हमार

तालाब में मछलियों के अचानक मरने की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि पानी की गुणवत्ता में गिरावट, ऑक्सीजन की कमी, रोग, विषाक्त पदार्थों का प्रभाव आदि। पवन महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम बनयानी, जनपद पंचायत बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के तालाब मे मछलियो के मरने की समस्या संबंधी जानकारी आज मिली है । समूह के सदस्यो से चर्चा, तालाब की तलहटी एवं मछलियों के व्यावहार से एसा प्रतीत हो रहा है कि पानी में अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट आदि हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढी हो और तालाब में घनी वनस्पति, मछलियों की अधिक संख्या, पानी का तापमान बढ़ना आदि की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ के वैज्ञानिक (मत्स्य पालन) डा. सतेंद्र कुमार ने बताया कि ग्रामीण तालाबों में ऑक्सीजन की कमी एक आम समस्या है। हर रोज सवेरे तालाब में अपनी मछलियों के चाल-ढाल पर नजर रखें। अगर मछलियां सतह पर आ कर मुंह खोल कर थूथने निकालती नजर आए तो समझ लीजिए आप के तालाब में ऑक्सीजन की कमी आ गई है।

मछलियों के तालाबों में ऑक्सीजन की कमी की समस्या वास्तव में तब उत्पन्न होती है जब उर्वरक के प्रयोग से तालाब में सूक्ष्म जीवाणुओं की भरमार हो जाती है । रात में रोशनी की उपस्थिति में ऑक्सीजन बनने की क्रिया थम जाती है और इस प्रकार जल में ऑक्सीजन कि जो भी घुली हुई जमा राशि उपलब्ध रहती है उसी से सूक्ष्म जीवाणुओं एवं

मछलियों को काम चलाना पड़ता है। फलस्वरूप मछलियों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वह परेशान होकर सतह पर आकर मुंह खोलने लगती हैं। विकट स्थिति में तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है।

ऑक्सीजन की कमी की समस्या वैसी स्थिति में भी हो जाती है जब लगातार कई दिनों तक आकाश में बादल छाए रहने के कारण धूप नहीं निकलता है अथवा तलछट पर अत्यधिक मात्रा में मलबा का जमाव हो जाता है।

मछलियों को बचाने अच्छे उत्पादन के लिए क्या करें

पवन महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम बनयानी, जनपद पंचायत बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के तालाब में मछलियों के मरने की समस्या पर कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डा. बी.एस. किरार निर्देशानुसार वैज्ञानिक (मत्स्य पालन) डा. सतेंद्र कुमार द्वारा जारी सम-सामयिक सलाह-

- कुछ इस प्रकार की युक्ति लगाएं जिससे तालाब के जल में हिलोरे उत्पन्न किए जा सके जैसे तालाब के पानी को हाथ से छलका कर या सतह पर डंडे मार कर तरंगे उत्पन्न करें, सम्भव हो तो तालाब में जल्दी-जल्दी या बार-बार जाल चलाएं आदि।
- तालाब में ताजा जल मिलाएं ध्यान रहे कि जल के साथ तालाब में अनावश्यक मछलियों का प्रवेश ना हो। अगर ताजे जल का अभाव हो तो ट्युब्यू पंप से तालाब के ही जल को फव्वारे की तरह परिसंचारित (रिसर्कुलेट) करें ।
- तालाब में पोटेशियम परमैग्नेट 300 ग्राम प्रति एकड़ अथवा 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से चुने का प्रयोग करें ।
- अनुकूल परिस्थिति आने तक तालाब में परिपूरक आहार तथा उर्वरक का प्रयोग बंद रखें।
- केले के तनों को छोटे-छोटे टुकड़े करके तालाब में बिखेरने से भी फायदा होता देखा गया है।
- तालाब में बार-बार जाल चलाएं।
- तालाब की नियमित सफाई करें।
- पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच करें।
- मछलियों की संख्या (संचयन दर) को नियंत्रित करें।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों का कृषि विज्ञान केंद्र में भ्रमण

जबलपुर। जागत गांव हमार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर मप्र के संयुक्त दल जिसमें डा जेके सोनी, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, डा. सहदेव कुकुवरदादरा, वैज्ञानिक अर्थिक वनस्पति शास्त्र एवं पादप आनुवंशिक संसाधन एवं डा़ हिमांशु महावर वैज्ञानिक सूक्ष्मजीव विज्ञान ने रीवा में दो दिवसीय दौरा किया।

भ्रमण के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रमुख डा. एके पांडेय के साथ डा. सी जे सिंह डा. के सी सिंह डा़ एके पटेल डा़ बीके तिवारी डा. अखिलेश कुमार डा. स्मिता सिंह डॉ के एस बघेल डा. संजय सिंह संदीप शर्मा डा. एम के मिश्रा, पुष्पेंद्र ने कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा द्वारा विभिन्न गाँवों के कृषकों के प्रक्षेत्र पर लगी चावल, अरहर और सोयाबीन की फसलों को देखा और किसानो के समस्याओं का निराकरण किया।

ग्राम खाजुआ कला में परम सुख चौरसिया के यहां अरहर और सोयाबीन का अवलोकन किया इसके बाद एक कृषक संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें विश्व खाद्य दिवस मनाने के साथ-साथ रमेश पटेल ने जैविक केले की खेती के सफलता की कहानी पर चर्चा किया।

किसानों ने बताई समस्या, वैज्ञानिकों ने बताया निराकरण

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने जंगली धान की समस्या बताई जिसे वैज्ञानिकों द्वारा निराकरण किया गया। ग्राम रीठी में कृषक राजेश पटेल की सोयाबीन की फसल का वैज्ञानिको द्वारा अवलोकन किया गया। तदुपरांत एक बृहद कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें समीपवर्ती गाँवों के किसानो ने भाग लिए जिसमें उनकी समस्याओं का निदान किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र में खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर से आए वैज्ञानिकों का केंद्र प्रमुख डा़ एके पांडेय द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। केंद में सभी वैज्ञानिको के साथ खरपतवार अनुसंधान निदेशालय से आए वैज्ञानिकों के साथ केंद्र की विभिन्न इकाइयों का भ्रमण कर रीवा जिले में केंद्र द्वारा कृषकों के बीच हो रहे कार्यों पर विशेष चर्चा हुई जिसमें उन्नत तकनीक को अपनाने पर रणनीति बनाई गई। जबलपुर से आए वैज्ञानिकों के संयुक्त दल द्वारा केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों के साथ किए जा रहे कार्यो की सराहना की गई।

कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में बीएससी कृषि टीकमगढ़ के छात्रों ने नर्सरी तैयार करने की तकनीक की बारीकियां भी सीखीं

फाइनल ईयर के छात्रों ने सीखा नर्सरी प्रबंधन एवं उन्नत सब्जी उत्पादन

नौगांव, छतरपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में बी.एस.सी. कृषि टीकमगढ़ के फाइनल ईयर के 36 छात्रों ने नर्सरी प्रबंधन, उन्नत सब्जी उत्पादन एवं सिंचाई तकनीकों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया यह सभी छात्र 6 माह तक ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कृषकों एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिको से संपर्क में रहकर ही कार्यों को सीखेंगे। इस प्रशिक्षण का आयोजन केवीके की प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वीणा पाणी श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में किया गया।

प्रशिक्षण में डॉ. कमलेश अहिरवार (वैज्ञानिक उद्यानिकी), रावे प्रभारी ने इस प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छात्रों को नर्सरी प्रबंधन की गहन जानकारी प्रदान कराना और प्रायोगिक कार्य के माध्यम से उनके कौशल को निखारना था। कार्यशाला में छात्रों को नर्सरी का सीमांकन, नर्सरी का सही लेआउट , फसल संग्रहालय का लेआउट तैयार करने की प्रक्रिया, उन्नत सब्जी उत्पादन तकनीक तथा थाला विधि से सिंचाई की तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यशाला के दौरान, डॉ. कमलेश अहिरवार (वैज्ञानिक उद्यानिकी),ने छात्रों को उन्नत सब्जी उत्पादन के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही विशेष रूप से नर्सरी प्रबंधन, सब्जियों की पौध तैयार करने, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उत्पादन में सुधार के आधुनिक तरीकों पर चर्चा की। इसके साथ ही, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता, श्री रोहित मिश्रा ने पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। छात्रों ने टमाटर, बैंगन, मिर्च के बीजों का नर्सरी में बुआई करना भी प्रायोगिक करके सीखा और इनकी नर्सरी तैयार करने की तकनीक की बारीकियां भी सीखी। इसके साथ ही फसल संग्रहालय में चुकंदर, मूली, गाजर, मेथी,पालक और धनिया जैसी प्रमुख सब्जियों की सीधी बुआई करना भी प्रायोगिक करके सीखा एवं अध्ययन किया। डॉ. कमलेश अहिरवार ने छात्रों को न केवल नर्सरी प्रबंधन सिखाया, बल्कि सब्जियों की सही तरीके से सिंचाई और पोषण प्रबंधन के बारे में भी व्यावहारिक जानकारी दी।

प्रशिक्षण का महत्व

डॉ. कमलेश अहिरवार ने बताया कि उन्नत सब्जी उत्पादन के लिए नर्सरी प्रबंधन और सिंचाई तकनीकें बेहद महत्वपूर्ण हैं। और कहा, 'अगर नर्सरी का प्रबंधन सही तरीके से किया जाए और सब्जियों की देखभाल वैज्ञानिक विधियों से की जाए, तो यह उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। इस अवसर पर डॉ. वीणा पाणी श्रीवास्तव ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा प्रायोगिक प्रशिक्षण छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने का अवसर देता है।

कार्यशाला में छात्रों की सक्रिय भागीदारी

कृषि विश्वविद्यालय, टीकमगढ़ से आए इन सभी छात्रों ने इस कार्यशाला में सि य भागीदारी निभाई और नर्सरी प्रबंधन एवं सब्जी उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर अपने सवाल भी पूछे जिसका समाधान भी किया गया। यह प्रशिक्षण कार्य म छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने उन्नत कृषि तकनीकों और नर्सरी प्रबंधन एवं फसल संग्रहालय में लेआउट एवं बीज बोनी के इस ज्ञान को अर्जित कर अपनी कुशलता को बढ़ाया।

अतिक्रमण से मुक्त हुई बंजर जमीन को उपजाऊ कर बनाई हरी बगिया पोषण वाटिका

प्रधानमंत्री ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं की प्रसंशा की

मध्यप्रदेश में हुए अच्छे कार्यों की पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की सराहना

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर मध्यप्रदेश में हुए अच्छे कार्यों का जिक्र किया। रविवार 29 सितम्बर को प्रसारित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत खौप की उन स्व-सहायता समूह की महिलाओं की प्रसंशा की, जिन्होंने प्रशासन द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराई गई 2 हैक्टेयर बंजर जमीन में फलदार ग्राफ्टेड 2300 पौधे लगाकर हरे-भरे फ्रूट फॉरेस्ट में तब्दील कर दिया। यह अनूठा कार्य ग्राम पंचायत खौप के स्व-सहायता समूह की 10 महिलाओं ने प्रशासन के सहयोग से कर दिखाया है। गांव की महिलाओं के इस बुलंद हौसले की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में की। इससे गांव की इन ग्रामीण महिलाओं का पूरे देश में नाम रौशन हुआ और वे अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रही हैं।

कैसे बना हरा-भरा फ्रूट फॉरेस्ट: नीति आयोग के डीसल्टिंग प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 2022 में शुरू किये गये इस महती काम में चंदेलकालीन तालाब की मिट्टी खोद कर मनरेगा योजना से संचालित कार्य में मिट्टी का उपयोग पौधरोपण कार्य में किया गया। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन पर वाटिका तैयार करने समूह की महिलाओं को साथ लेकर पौधरोपण किया गया। साथ ही अटल भूजल योजना अंतर्गत सिंचाई के लिए ड्रिप एरिगेशन की सुचारू व्यवस्था भी की गई। इन पूरे प्रबंधों की देख-रेख समूह की 10 महिलाओं ने की। समूह की अध्यक्ष कौशल्या रजक, सचिव पार्वती रजक, सदस्य फूला रजक, जानकी रजक, ममता रायकवार, हल्की बाई रजक, भगवती कुशवाहा, रचना कुशवाहा, रामदेवी रजक एवं कुसुम रजक है।

शारदा स्व-सहायता समूह के फिश पार्लर को भी मिली सराहना

प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में डिंडौरी जिले के ग्राम रयपुरा के शारदा स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा संचालित फिश पार्लर को सराहा। समूह की अध्यक्ष श्रीमती शारदा धुर्वे बताती हैं कि वर्ष 2014 में मत्स्य विभाग द्वारा रयपुरा जलाशय का पट्टा समूह को 10 वर्ष के लिये दिया गया। हमारे समूह की महिलाओं ने मिलकर जलाशय के रख-रखाव के साथ मत्स्य उत्पादन भी प्रारंभ किया। वे बताती है कि शुरू में हम मछली की बिक्री के लिए अलग-अलग हाट बाजार में जाते थे, जिला प्रशासन डिंडौरी के सहयोग से दीदी फिश पार्लर का शुभारंभ इसी वर्ष गणतंत्र दिवस पर किया गया। जिससे हमारी आमदनी में वृद्धि हुई।

फ्रूट फॉरेस्ट की सब्जियों का उपयोग मध्यान्ह भोजन में

ग्राम खौप के फ्रूट फॉरेस्ट में फलदार पौधे एवं सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ की सब्जियों का उपयोग माध्यमिक शाला के मध्यान्ह भोजन के लिए किया जाता है। सब्जियों को बेचकर प्राप्त होने वाली आय से समूह की महिलाओं की आमदनी में वृद्धि भी हुई है।

12 दीदियाँ कर रहीं मत्स्य उत्पादन और विक्री भी

अध्यक्ष ने बताया कि समूह से जुड़ी 12 दीदियाँ मत्स्य उत्पादन का कार्य कर दीदी पार्लर के माध्यम से मछली की बिक्री कर रही हैं। मत्स्य विभाग से प्राप्त बीजों का उपयोग कर 10 हैक्टेयर के जलाशय में मत्स्य उत्पादन के कार्य को बढ़ाया जा रहा है। मछली पालन के साथ जलाशय के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। जलाशय में रोहू, कतला, करचा, नरेनी जैसी मत्स्य प्रजातियों का उत्पादन जारी है। उत्पादित मछलियों का प्र-संस्करण कर प्रतिदिन दीदी फिश पार्लर में लाया जाता है, जहां मछलियों को बेचा जाता है। शारदा समूह की सचिव श्रीमती सुमन धूमकेती ने बताया कि हम पहले मजदूरी कर जीवनयापन करते थे, जिससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2014 से मछली पालन करना शुरू किया, इसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ सम्मान में भी वृद्धि हुई है।

बुरहानपुर के बसाली गांव को पर्यटन स्थल के रूप में किया जा रहा विकसित

बुरहानपुर। जागत गांव हमार

बुरहानपुर ब्लॉक के बसाली गांव के पास एक अत्यंत मनोरम प्राकृतिक झरना है, जो लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोग इस बरसाती झरने को ''बसाली झरना'' के नाम से जानते हैं। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य एवं बारिश से फैली हरियाली के बीच यह झरना इतना मनमोहक है कि पर्यटक खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाते। इस क्षेत्र की बढ़ रही लोकप्रियता को देखते हुए बसाली के इस झरने तक लोगों की सहजता से पहुँच बढ़ाने एवं पर्यटन विकास के लिये जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना से एक प्रभावी कार्य-योजना तैयार की गई है। इसमें विकास कार्यों के लिये 60 लाख रूपये मंजूर किये गये हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय आबादी बहुल गांवों के विकास के लिये 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना' चलाई जा रही है। इस योजना से बुरहानपुर जिले में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भी कई प्रकार के विकास कार्य कराये जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों की सुविधाओं में इजाफा तो हो ही रहा है, साथ ही पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

पर्यटकों के लिये रहवासी कॉटेज का निर्माण

योजना में स्वीकृत राशि से बसाली झरने के पास ही पर्यटकों के रूकने के लिए चार रहवासी कॉटेज बनाये जा रहे हैं। झरने तक पहुंच मार्ग की मरम्मत की जा रही है। यहां आने वाले पर्यटकों के खान-पान की व्यवस्था के लिये एक कैंटीन तैयार की जा रही है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बसाली झरने के पास पहाड़ी रास्तों में %ट्रेकिंग रूट% तैयार करने की भी योजना है। इस ट्रेकिंग रूट से पर्यटक जंगल की सैर भी कर सकेंगे, जो उन्हें प्रकृति के और ज्यादा करीब ले जायेगी। इन सभी प्रयासों से यह झरना एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में अपनी पहचान बनायेगा।

आजीविका मिशन की दीदियां बनेंगी टूरिस्ट गाइड

बसाली झरने के पास तैयार की जा रही कैंटीन स्व-सहायता समूह की महिलाएं चलायेंगी। इससे उन्हें रोजगार मिलेगा, साथ ही वे आत्म-निर्भर भी बनेंगी। बुरहानपुर जिले में अन्य राज्यों व जिलों से आने वाले बाहरी पर्यटकों की सुविधा के लिए स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 'टूरिस्ट गाइड' के रूप में तैयार करने की तैयारी है। बसाली के स्व-सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका मिशन से टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके बाद इन्हें परिचय-पत्र भी दिये जाएंगे, जो इन्हें प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड की पहचान दिलायेगा। यह काम इसी साल के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा।

जन, जल, जंगल-जमीन के अधिकारों को समझ

जन, जल, जंगल-जमीन के अधिकारों को समझ रहे जनजातीय परिवार

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत जनजातियों को जन, जल, जंगल, जमीन और श्रमिकों के अधिकारों की जानकारी देकर इनके संरक्षण एवं जनजातीय सांस्कृतिक परम्पराओं की सुरक्षा के लिये अब से करीब दो साल पहले एक बड़ा कदम उठाया गया। जनजातीय समुदाय के आद्य गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुण्डा के जन्म-दिवस पर मध्यप्रदेश में 15 नवंबर 2022 को पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) नियम-2022 या कहें पेसा एक्ट लागू किया गया।

मध्यप्रदेश के 20 जिलो के 88 विकासखंडों की 5133 ग्राम पंचायत क्षेत्रों के 11 हजार 596 गांव पेसा क्षेत्र में आते हैं। प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, अनूपपुर और बड़वानी पूर्ण पेसा जिले हैं। वहीं बालाघाट बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, खंडवा, नर्मदापुरम, खरगौन, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी उमरिया एवं रतलाम आंशिक पेसा जिलो की श्रेणी में आते हैं।

पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन से अनूपपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यहां ग्रामीणों को उनके अधिकारों एवं रोजगार के बारे में जानकारी देकर गांव में ही रोजगार तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। अनूपपुर जिले की जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ की ग्राम पंचायत दमेहडी में पेसा अधिनियम का सकारात्मक प्रभाव साफ-साफ देखने को मिल रहा है। यहां के जनजातीय समुदाय-जन, जल, जंगल एवं जमीन के अधिकार को समझ चुके हैं तथा शासन की मंशा के अनुरूप पेसा अधिनियम से अपनी उन्नति की राह पर अग्रसर हो रहे हैं। यहां के ग्रामीण आपसी भाईचारे से मिल-जुलकर रह रहे हैं। यहां लोगों का अपने जंगल व वन्यजीवों के साथ साहचर्य जीवन व्यवहार भी बेहद सौहार्दपूर्ण हो गया है।

गांव के छोटे-मोटे विवादों को मिलजुल कर गांव में ही सुलझा लिया जाता है

पेसा अधिनियम लागू होने के पहले इस ग्राम पंचायत में बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हुआ करती थीं। लोग हमेशा ही आपसी लड़ाई-झगड़े और कोर्ट-कचहरी में फंसे रहते थे। पेसा अधिनियम के कारण गांव की स्थिति में बदलाव हुआ है। अब गांव के छोटे-मोटे विवादों को मिल-बैठकर गांव में ही सुलझा लिया जाता है। यहां के ग्रामीण बताते हैं कि पहले पुलिस केस होता था, उसके बाद वकीलों तथा कोर्ट के चक्कर लगा-लगाकर आखिरी विकल्प समझौता करना ही होता था, तब तक हमें बेहद परेशान होना पड़ता था। अब इन मुसीबतों से हमें छुटकारा मिल गया है। ग्राम दमेहडी के लोगों का कहना है कि जब से पेसा एक्ट लागू हुआ है, तब से गांव में शांति, उन्नति, प्रगति एवं आपसी भाईचारे का माहौल कायम है। अब गांव का झगड़ा विवाद निवारण समिति द्वारा आसानी से सुलझा लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति थाने चला भी जाता है, तो लोकल थाने की पुलिस द्वारा शांति एवं विवाद निवारण समिति के सदस्यों को सूचना दी जाती है। संज्ञान में आते ही ग्राम सभा द्वारा उस व्यक्ति को समझाकर मामले का निपटारा गांव में ही कर लिया।

राज्यपाल की अध्यक्षता में ग्वालियर में हुआ कृषि विश्वविद्यालय का दशम दीक्षांत समारोह

कृषि विद्यार्थी किसानों की खेती संबंधी जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान दें: पटेल

समारोह में 4 मानद उपाधि, 7 गोल्ड मैडल एवं 979 उपाधियाँ प्रदान की गईं

ग्वालियर। जागत गांव हमार

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कृषि विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि पारंपरिक ज्ञान एवं आधुनिक ज्ञान-विज्ञान व तकनीकी कौशल का उपयोग कर किसानों की खेती संबंधी जटिल समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दें। साथ ही वंचित एवं दूरस्थ अंचलों तक उन्नत कृषि तकनीक पहुँचाने के प्रयास भी प्रमुखता से करें। राज्यपाल पटेल गत दिवस ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दशम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपाधियाँ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके गुरुजनों व पालकों को बधाई व शुभकामनाएं प्रदान कीं। कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में यह दीक्षांत समारोह डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के कुलाधिपति प्रो. पी एल गौतम व भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला, विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्यगण एवं आचार्य मंचासीन थे।

दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात कृषि वैज्ञानिक जगदीश कुमार लड्ढा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ओ पी श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिक पी एम गौर एवं जैविक खेती में नाम कमा रहे वत्सल दीपक सजदे को कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि देकर सम्मानित किया गया।

साथ ही 7 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक व 4 विद्यार्थियों को सिरताज बहादुर सिन्हा स्मृति नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2023-24 के कुल 979 विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में उपाधियाँ प्रदान की गईं। इनमें 48 शोधार्थियों को पीएचडी, 666 को स्नातक एवं 265 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधियाँ प्रदान की गईं। इस अवसर पर दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन भी किया गया।

चुनौतियों का सामना करने के लिये किसानों को सक्षम बनाना होगा

राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की दिशा में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में उद्यमों की संभावनाओं को पहचानने में विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। साथ ही नए विचारों व नवाचारों के द्वारा सामान्य किसानों को उत्पादक से उद्यमी बनाने के प्रयास करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को किसानों की बुद्धिमत्ता और कृषि प्रोफेशनल्स के कौशल के बीच की साझेदारी का मंच बनकर सबके साथ, सबके विकास व सबके विश्वास की अवधारणा के साथ कृषि के विकास में सहयोग करने के लिये आगे आना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि की अनेक उपलब्धियों के बाबजूद कृषि जोतों का घटता आकार, जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों का लगातार क्षरण अभी भी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिये किसानों को सक्षम बनाना होगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर अनुसंधान और प्रयास करने की जरूरत होगी। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा युवाओं की सहभागिता से आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की पहल की है। विकसित भारत बनाने के लिये कृषि क्षेत्र में आय और रोजगार की वृद्धि के द्वारा न्याय संगत व समावेशी ग्रामीण विकास की अपार संभावनाओं को अमलीजामा पहनाया जा सकता है। राज्यपाल पटेल ने कृषि विद्यार्थियों का आह्वान किया कि अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज की सबसे पीछे की पंक्ति और पिछड़े व्यक्ति की खुशहाली के लिये करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिये आज विशेष महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन आप सबको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपको यह उपलब्धि दिलाने में समाज का भी कहीं न कहीं योगदान जरूर है। समाज व देश की सेवा कर यह ऋण लौटाया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा उपाधियाँ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साह और ऊर्ज देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। साथ ही भरोसा भी मिला है कि आप सबके माध्यम से विकसित और स्वर्णिम भारत के निर्माण का सपना साकार होगा।

कृषि विद्यार्थी रोजगार पाने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें: प्रो. पीएल गौतम

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलाधिपति प्रो. पी एल गौतम ने कहा कि देश में कृषि के क्षेत्र में जिस तरह की क्रांति आई है, उससे हम सब गौरवान्वित हैं। लेकिन जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों की कमी, खेती की बढ़ती लागत व युवकों का खेती से रूझान कम होना ऐसी चुनौतियां हैं, इनसे निपटने के प्रयास भी विश्वविद्यालयों को करने होंगे। इसके लिये ढांचे को और सुदृढ़ कर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने गुणवत्तायुक्त कृषि शिक्षा, शोध व उसके प्रसार पर बल दिया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कृषि आयोग गठित करने की आवश्यकता बताई। प्रो. गौतम ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में हो रहे अनुसंधान और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में स्थापित हुए नए-नए आयाम की सराहना की। कार्य म के विशिष्ट अतिथि एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ दिनेश कुलकर्णी ने कहा कि यह बात सही है कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी न के बराबर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कृषि विद्यार्थी अपने ज्ञान का उपयोग खेती में करने के बजाय नौकरी की ओर ज्यादा रूख करते हैं। यह विचारणीय है कि कृषि की शिक्षा लेने के बाद विद्यार्थी नौकरी करते हैं और जिन्हें कृषि की शिक्षा नहीं मिली वह खेती करती है। इसलिए इसकी महती आवश्यकता है कि कृषि विद्यार्थी रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि उन्नत खेती व खेती से संबंधित उद्यम स्थापित कर रोजगार देने वाले बनें। इससे निश्चित ही औरों को प्रेरणा मिलेगी और खेती लाभ का धंधा बनेगा।

विवि में 11 अनुसंधान परियोजनाएं प्रचलन में हैं: कुलपति प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला

स्वागत उद्बोधन एवं दीक्षोपदेश विवि के कुलपति प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला ने दिया। उन्होंने विवि की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। प्रो. शुक्ला ने जानकारी दी कि 2018 से 2023-24 तक की उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया गया है। गेहूं की प्रजाति को भी भाभा ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक केंद्र के साथ मिलकर तैयार किया गया है। विवि में 11 अनुसंधान परियोजनाएं प्रचलन में हैं जिसमें हवा में आलू बीज उत्पादन के लिए 229 लाख की यह परियोजना है। वहीं सब्जियां के बीज हेतु 416 लाख रुपए की हाइब्रिड बीज के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने तथा सोलर बेस्ड इंटेंसिव परियोजना ग्वालियर में लागू की गई है। ग्रीन एवं एनर्जी ऑडिट में सफलता प्राप्त की है।

इन्हे मिला स्वर्ण पदक

दीक्षांत समारोह में कृषि स्नातक 04 छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। जिनमें कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर की कु. साक्षी, कृषि महाविद्यालय, सीहोर की कु. श्रुति तोमर, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर के अमित बिरगोदिया एवं कु. गार्गा त्रिपाठी शामिल हैं। कृषि स्नातकोत्तर मंदसौर की कु. श्रेजल तिवारी एवं सीहोर की निमिषा माहेश्वरी एवं पी.एच.डी. में धीरज सिंह, ग्वालियर को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।

इन्हे मिले सरताज बहादुर सिन्हा स्मृति अवार्ड

हिमांशु नागर, विशाल गुप्ता, रामस्वरूप लमरोर एवं कु. निमिषा माहेश्वरी को सरताज बहादुर सिन्हा स्मृति अवार्ड प्रदान किये गये।

राज्यपाल ने शोधार्थी आशुतोष मिश्रा की पुस्तक 'जैविक कृषि' का किया विमोचन

चित्रकूट। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विवि चित्रकूट के 12वां दीक्षांत समारोह की शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं विवि के कुलाधिपति मंगू भाई पटेल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदर सिंह परमार मंत्री उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग मप्र शासन और विवि के कुलगुरु प्रोफेसर भरत मिश्र की उपस्थिति में कुलाधिपति द्वारा कृषि संकाय के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग में शोध कार्य कर रहे आशुतोष मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक जैविक कृषि का विमोचन किया गया, जो आज के परिप्रेक्ष्य में यह पुस्तक कृषि छात्रों एवं किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति के द्वारा हमारा देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ, परन्तु इसका प्रभाव मृदा के नैसर्गिक उर्वरा शक्ति में गिरावट के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर भी पड़ा। मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आने से निसंदेह खाद्यान्न उत्पादन की निरंतरता में भी गिरावट आई, विभिन्न रासायनिक उर्वरक को, रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक शाकनाशियों, के अंधाधुंध प्रयोग के साथ ही साथ भूमिगत जल भी प्रदूषित हो गया है, जिसका प्रभाव पशुओं एवं मानव जाति में बीपी, शुगर एवं कैंसर का प्रादुर्भाव हुआ है। इन दुष्परिणामों से छुटकारा पाने के लिए, एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं टिकाऊ कृषि उत्पादन हेतु जैविक कृषि पुस्तक किसानों के लिए एक उत्तम एवं प्रभावशाली विकल्प के रूप में सहायक होगा।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)